पाँचवा-स्तम्भ

CUTS International

हमारा मुख-पत्र

वर्ष 13, अंक 1/2012

...✍ सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार

सौ फीसदी लोग भ्रष्टाचार पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहते हैं 'इसका सबसे ज्यादा नुकसान गरीब भुगत रहे हैं।' लेकिन उन्हें अफसोस इस पर है कि केन्द्र और राज्य सरकारें इस सच्चाई से पूरी तरह वाकिफ होने के बावजूद सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने में लगी हैं। सरकारें सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही का राग तो अलापती है, जबकि असलियत इससे कोसों दूर है। हाल ही कट्स द्वारा किए गए हालात सर्वे में लोगों के ऐसे कई विचार उभरकर सामने आए हैं।

गरीबों के लिए बनी महानरेगा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में धड़ल्ले से हो रही लूट इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। गरीबों के नाम पर चलाई गई 40 हजार करोड़ रुपए की सबसे बड़ी योजना का हश्र देंखे, सरकारी आंकड़ें कहते हैं कि इस योजना में 55 फीसदी ही हकदारों तक पहुंचता है। यानि करीब 16 से 17 हजार करोड़ रुपए हकदारों तक नहीं पहुंचते। लोगों का कहना है कि हालात तो इससे कई गुना बदतर है।

यही हाल गरीबों के लिए बनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का है। राजस्थान में गरीबों के केरोसिन तेल में ही करोड़ों का खेल सामने आया। राज्य के खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग की रिपोर्ट बताती है कि आवंटित हुए 51 करोड़ लीटर केरोसिन में से 30 करोड़ लीटर कालाबाजारी के भेंट चढ़ जाता है। इस घोटाले की रकम हर साल करीब 921 करोड़ रुपए होती है।

भ्रष्टाचार से भारत की छवि विदेशों तक में खराब है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताजा रिपोर्ट बता रही है कि भारत में लगातार पारदर्शिता घट रही है। भारत पहले 72वें स्थान पर था, जो अब पारदर्शिता के घटते 95वें स्थान पर आ गया है। इसके लिए पिछले दिनों सामने आए बड़े घोटाले, काला धन उजागर करने और जनलोकपाल पर नानुकुर सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। लेकिन सरकार को इनकी जरा भी चिन्ता नहीं है?

इस अंक में...

- गरीबों के तेल में 921 करोड़ का खेल 4
- देश में नेताओं का नैतिक पतन 5
- भ्रष्टों के खिलाफ कोर्ट का अहम फैसला 6
- योजना आयोग ने भर दी झोली 7
- सौर ऊर्जा आवंटन में प्रदेश सबसे आगे 8

महानरेगा योजना की कमियों को दूर करना आवश्यक

प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य एवं राजस्थान योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष प्रो. वी.एस.व्यास ने कहा है कि महानरेगा एक महत्वपूर्ण योजना है। पूरे विश्व में इस तरह की रोजगार देने वाली योजना नहीं है, जिसमें 100 दिन का रोजगार देना सुनिश्चित किया गया हो। उन्होंने योजना में आने वाली बाधाओं और विफलताओं पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि समय पर यदि योजना के क्रियान्वयन में सुधार नहीं लाए गए तो यह योजना दम तोड़ देगी।

उन्होंने उक्त विचार 'कट्स' द्वारा 14 मार्च को जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय प्रचार-प्रसार एवं पैरवी बैठक में मुख्य अतिथि रूप में व्यक्त करते हुए योजना में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

बैठक में राज्य विधानसभा सदस्य राव राजेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में विधायकों व सांसदों द्वारा किए गए विकास कार्यों की जिम्मेदारी किसी भी विभाग के द्वारा नहीं ली जा रही। इससे करोड़ों रुपए व्यर्थ चले जाते हैं। प्रदेश में एक ऐसा तंत्र स्थापित होना चाहिए जो इन विकास कार्यों का लेखा-जोखा तैयार कर सके।

इस अवसर पर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव एम.एल.मेहता ने सुशासन की व्याख्या करते हुए कहा कि इसके मुख्य घटक जन सहभागिता, गुणवत्तापूर्ण सेवाएं व आमजन तक सूचनाओं की पहुंच है। उन्होंने संसद व विधानसभाओं में घटते कार्यकाल पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जन प्रतिनिधियों की जनता के प्रति जवाबदेहिता कम होती जा रही है।

इन्स्टीट्यूट ऑफ डवलपमेंट स्टडीज के निदेशक सुरजीत सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने महानरेगा की मूल्यांकन रिपोर्टों और महाराष्ट्र मॉडल से कोई सीख नहीं ली, जिसका परिणाम है कि आमजन में महानरेगा के प्रति स्वामित्व की भावना का अभाव है।

कट्स के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने परियोजना की जानकारी देते हुए बताया कि कट्स द्वारा सुशासन की दिशा में प्रयुक्त किए गए कम्यूनिटी स्कोर कार्ड जैसे उपकरणों के प्रयोग से किस प्रकार विभिन्न योजनाओं में अपेक्षित सुधार सामने आए हैं। कार्यक्रम में सरकारी विभागों व मीडिया प्रतिनिधियों सहित प्रदेश के 66 स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

जमीनी स्तर तक पहुंचे वित्तीय अधिकारों की जानकारी

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर 'कट्स' द्वारा 16 मार्च 2012 को 'हमारा पैसा हमारे अधिकारः वित्तीय सेवाओं में उपभोक्ता' विषयक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बैंकिंग लोकपाल कार्यालय जयपुर की उपमुख्य प्रबन्धक श्रीमती के. सुन्दरी ने बैंकिंग लोकपाल और भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यप्रणाली और वित्तीय सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि अब ग्रामीण जनमानस को बैंकों से जोड़ने के लिए तेज प्रयास किए जा रहे हैं।

राज्य सरकार के प्रवर्तन अधिकारी संजय झाला ने उपभोक्ताओं को बेहद सावधानी से अपना धन निवेश करने व लेन-देन करने का सुझाव दिया। कार्यशाला में विभिन्न बैंकों के प्रबंधकों ने उपभोक्ता हितार्थ कार्यक्रमों के विषय में विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला के प्रारंभ में कट्स निदेशक जॉर्ज चेरियन ने अपने सम्बोधन में कहा कि आज भी उपभोक्ताओं का एक बड़ा समुदाय बैंकों और वित्तीय सुविधाओं से वंचित है और वे अपने अधिकारों से वाकिफ तक नहीं हैं। कार्यशाला में स्वयंसेवी संस्थाओं, मीडिया के करीब 70 प्रतिभागियों ने उत्साह से भाग लिया।

देश की सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए 65 फीसदी लोगों ने अन्ना हजारे के जनलोकपाल बिल को सही व कारगर उपाय माना है। इसके अलावा 22 फीसदी लोगों ने भी अन्ना के लोकपाल बिल को आंशिक रूप से सही बताया। इस प्रकार राजस्थान के 87 फीसदी लोग अन्ना के जन लोकपाल बिल को अपना समर्थन देते हैं।

उक्त तथ्य कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी 'कट्स' द्वारा प्रदेश में कराए गए 'हालात सर्वे' नामक सर्वेक्षण से सामने आए हैं। यह सर्वे केन्द्रीय सरकार के काम-काज का आंकलन, खास ज्वलंत समस्याओं जैसे भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी तथा लोकपाल बिल आदि पर राजस्थान के लोगों की प्रतिक्रिया जानने के मकसद से किया गया। सर्वे में राज्य के सभी जाति, समुदाय व वर्गों के 554 लोगों ने अपनी राय व्यक्त की है।

क्या भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए अन्ना हजारे का जनलोकपाल बिल सही उपाय है?

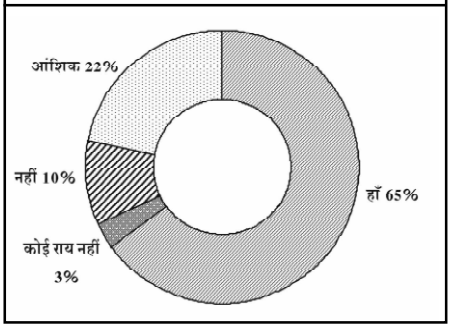

सर्वे के विश्लेषण पर यह उभर कर आया कि प्रदेश का चाहे शहरी इलाका हो या ग्रामीण, 73 फीसदी लोगों ने लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री, न्यायपालिका, सीबीआई सहित सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को लाना उचित ठहराया है। इसके अलावा 13 फीसदी लोग भी आंशिक रूप से इसी पक्ष में शामिल हैं।

लोगों की नजर में वर्तमान में देश की सबसे ज्वलंत समस्या भ्रष्टाचार है। इस पर100 फीसदी लोगों ने अपनी मुहर लगाई। वहीं वरीयता क्रम में क्रमशः 84 फीसदी ने बेरोजगारी, 80 फीसदी ने आतंकवाद और 78 फीसदी लोगों ने मंहगाई को मुख्य समस्या के रूप में उजागर किया है। 63 फीसदी लोग भ्रष्टाचार और कालाबाजारी को देश में महंगाई बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराते हैं। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में 47 फीसदी लोगों ने बताया कि महंगाई पर नियंत्रण के लिए यूपीए सरकार द्वारा उठाए गए कदम कुछ हद तक ही कारगर सिद्ध हुए हैं।

केन्द्र सरकार के खाद्य सुरक्षा विधेयक पर ली गई राय के अनुसार मात्र 12.6 फीसदी लोगों का मानना है कि इससे निर्धन व कमजोर वर्ग के लोगों को भूख से निजात मिल जाएगी। साथ ही 44.7 फीसदी ने इसे कुछ हद तक कारगर माना है। जबकि 39.7 फीसदी लोग यह मानते हैं कि इससे गरीबों व कमजोर वर्ग के लोगों को पूरी तरह भूख से निजात नहीं मिल पाएगी।

केन्द्र सरकार द्वारा लाए जाने वाले खाद्य सुरक्षा एवं 'सिटीजन चार्टर' विधेयक को ज्यादातर लोगों ने एक सराहनीय कदम बताया।

यह भी आया सामने

- मात्र 11 फीसदी लोगों ने ही केन्द्र सरकार द्वारा तैयार किए गए लोकपाल बिल को ठीक माना है तथा 21 फीसदी इसे आंशिक रूप से सही ठहराते हैं।
- 37.7 फीसदी लोगों ने भ्रष्टाचार, 25.5 फीसदी ने काला बाजारी, 17.9 फीसदी ने सरकारी प्रयासों की कमी, 12.5 फीसदी ने काला धन विदेशी बैंकों में जमा होने तथा 6.4 फीसदी लोगों ने आर्थिक मंदी को महंगाई बढ़ने के लिए जिम्मेदार ठहराया है।
- 48.6 फीसदी लोग नहीं मानते कि यूपीए सरकार सही दिशा में काम कर रही है।
- 36 फीसदी लोग प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह को सफल नहीं मानते, 42 फीसदी लोग कुछ हद तक उन्हें सफल मानते हैं। मात्र 18 फीसदी ने ही उन्हें पूरी तरह सफल प्रधानमंत्री बताया है।
- 60 फीसदी लोग वर्तमान की सरकारी राशन व्यवस्था से संतुष्ठ नहीं हैं। उनका मानना है कि खाद्य सुरक्षा विधेयक लागू करने के साथ इस व्यवस्था में सुधार करना जरूरी है। तभी निर्धन व कमजोर वर्ग को भूख से निजात मिल सकेगी।

बीसलपुर परियोजना में घपला

बीसलपुर परियोजना में मिट्टी खुदाई, पाइप लाइन टेस्टिंग में तो करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं, साथ ही आरयूआईडीपी ने सर्विस टैक्स के नाम पर गलत भुगतान करके करीब एक करोड़ रुपए की चपत सरकारी कोष को लगाई है। एसीबी सूत्रों के मुताबिक बीसलपुर परियोजना के 480 करोड़ रुपए के कामों का ठेका लार्सन एण्ड टूर्बो फर्म को मिला।

इस फर्म ने दूसरी फर्मों से भी परियोजना से जुड़े काम करवाए। इन कार्यों पर लगने वाले सर्विस टैक्स आरयूआईडीपी को नहीं देना था, लेकिन आरयूआईडीपी के तत्कालीन मुख्य अभियंता मदनलाल मीणा, वरिष्ठ लेखाधिकारी सतीश गोयल और श्यामलाल अग्रवाल ने मिलीभगत करके इन फर्मों को नियम विरुद्ध तरीके से करीब 97 लाख रुपए का भुगतान कर दिया। नियमों के अनुसार विभाग को उन्हीं सेवाओं पर सेवाकर भुगतान करना था, जिनसे विभाग ने सीधी सेवाएं ली थीं।

(रा.प., 01.01.12)

वाटर सेस का पैसा मनमर्जी से खर्च

जल स्त्रोतों के संरक्षण और प्रदूषण दूर करने के लिए वसूला गया करीब 56 करोड़ रुपए के वाटर सैस का पैसा प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अफसरों ने मनमर्जी से खर्च कर दिया। जबकि नियमानुसार वे इस राशि में से केवल 25 प्रतिशत पैसा ही ऑफिस और संस्थापन खर्च में काम ले सकते थे।

सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई एक जानकारी से यह खुलासा हुआ है कि विभाग के अफसरों ने मनमर्जी से इस पैसे का उपयोग आरएंडडी, संस्थापन, ऑफिस, केपिटल खर्च और अन्य कामों में किया है। इस पैसे का उपयोग लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने व प्रदूषण रोकने की गतिविधियों में होना चाहिए।

(दै.भा., 28.03.12)

अनियमित था देश का दलहन आयात

देश का दलहन आयात कितना अनियमित था और उसके उपरान्त कार्यप्रणाली कितनी अनियमित थी, इसका खुलासा सीएजी की ओर से तैयार की गई एक नवीनतम रिपोर्ट में हुआ है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में दलहन आयात तो इसलिए किया गया था कि घरेलू बाजार में दलहनों की कीमतें चूंकि अधिक चल रही थी, लिहाजा दालों का आयात कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए आम आदमी तक दालों को सुलभ कराया जाए। लेकिन इस कार्यप्रणाली में काफी विसंगतियां देखने को मिली।

सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया है कि इसका अधिकतर लाभ निजी करोबारियों ने उठाया। खास बात यह भी रही कि 2006 से 2011 के बीच 53.10 लाख टन आयात लक्ष्य की तुलना में 30.04 लाख टन ही आयात हुआ और उसमें से 26.95 लाख टन दालों का आयात करने वाली एजेंसियों ने विक्रय किया। इससे सरकारी एजेंसियों को 1201.32 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। *(न.नु., 03.01.12)*

आमदनी अठन्नी खर्चा...?

परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने जयपुर शहर के बाजारों के नो-पार्किंग क्षेत्रों से वाहन उठाने के लिए आमदनी से ज्यादा का खर्चा कर डाला। सूचना के अधिकार के तहत हुए इस खुलासे के मुताबिक शहर में नो-पार्किंग से उठाए वाहनों से मिलने वाली जुर्माना राशि से लाखों रुपए अधिक का भुगतान वाहन उठाने वाली आदित्य ब्रेक डाउन क्रेन कम्पनी को किया जा रहा है। पिछले तीन सालों के आंकडों पर गौर किया जाए तो विभाग को कमाई की बजाय लाखों रुपए की चपत लग रही है।

तीन साल में क्रेन कम्पनी को 77 लाख 16 हजार 287 रुपए गए हैं, जबकि जुर्माना राशि 41 लाख 58 हजार 299 रुपए प्राप्त हुई। देखा जाए तो विभाग को 25 लाख रुपए का घाटा हुआ है। प्रमुख शासन सचिव यातायात का कहना है कि क्रेन से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को भी उठाया जाता है इसलिए खर्च अधिक आता है। *(रा.प., 07.02.12)*

26 लाख गड़बड़ियों का कोई जवाब नहीं

प्रदेश की पंचायतें, स्थानीय निकाय, स्वायत्तशासी संस्थाएं और कृषि उपज मण्डियां अनियमितताओं की खान साबित हो रही हैं। इन संस्थाओं की 25 लाख 80 हजार से ज्यादा गड़बड़ियां फाइलों में कैद हैं। इनमें 24 करोड़ रुपए के ऐसे गबन भी शामिल हैं, जिनकी वसूली तक नहीं हो पा रही। गड़बड़ियों के आंकड़े में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की है।

यह चौंकाने वाला आंकड़ा इन संस्थाओं की ऑडिट करने वाले स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग की रिपोर्ट में सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार 31 दिसम्बर 2011 तक पंचायतीराज संस्थाओं, जेडीए और नगर निगमों, परिषदों, आवासन मण्डल व कृषि उपज मण्डियों तथा कृषि विपणन बोर्ड जैसी जनप्रतिनिधियों से जुड़ी संस्थाओं के 25 लाख 80 हजार से ज्यादा ऑडिट ऑब्जेक्शन लम्बित थे। *(रा.प., 30.03.12)*

आलमारी में बन्द सुशासन

प्रदेश में अगर एक दशक पहले प्रशासनिक सुधार आयोग के सुझावों को लागू किया जाता तो सुशासन के नारे को हकीकत में बदला जा सकता था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पिछले कार्यकाल में बनाए गए प्रशासनिक सुधार आयोग की 11 रिपोर्टों में से अधिकांश पर आज तक अमल नहीं हुआ है।

आयोग ने राजस्व विभाग, पुलिस, जन अभियोग व लोक शिकायत निवारण, पंचायतीराज और तबादला नीति पर 11 रिपोर्टें सरकार को सौंपी थी। जन अभियोग निराकरण का पूरा तंत्र विकसित कर जनता की शिकायतों के निवारण का तौर-तरीका सुझाया गया था। लेकिन 2002 में सौंपी इन सिफारिशों पर अमल नहीं हुआ और आज भी विभागों की आलमारियों में बन्द पड़ी हैं।

(दै.भा., 08.02.21)

अफसरों ने निजी काम में फूंका तेल

जनता की खून पसीने की कमाई को अफसर निजी कामों में उड़ा रहे हैं। ये सरकारी काम के लिए मिली गाड़ियों का इस्तेमाल अपने बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने, पत्नी को खरीददारी कराने, मेहमानों को पिकनिक पर ले जाने के साथ-साथ लम्बी दूरी की यात्राओं में भी करते हैं। यह खुलासा स्टेट मोटर गैराज की ऑडिट में हुआ है।

स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग के आंतरिक जांच दल द्वारा किए गए ऑडिट नोट में बताया गया है कि अफसरों द्वारा 86 लाख 74 हजार 673 रुपए का सरकारी पेट्रोल-डीजल निजी कामों में फूंका है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक अफसर गाड़ियों की लॉगबुक भी जीएडी के नियमानुसार नहीं भरते। लॉगबुक नियम से नहीं भरने में सीएम व सचिवालय पूल अव्वल है। इनको दी गाड़ियों में कौन अफसर चलाते हैं यह भी तय नहीं है। गाड़ियों का सबसे ज्यादा दुरुपयोग यहीं हैं। गौरतलब यह है कि मामले में सामान्य प्रशासन नें भी चुप्पी ओढ़ ली है। *(रा.प., 04.02.12, 17.02.12)*

गरीबों के तेल में 921 करोड़ का खेल

प्रदेश में सब्सिडी पर मिलने वाले केरोसिन तेल में हर साल करीब 921 करोड़ रुपए का महाघोटाला हो जाता है। हालात यह है कि गरीबों के लिए प्रदेश में हर साल 51 करोड़ लीटर से अधिक तेल आंवटित होता है, उसमें से 30 करोड़ लीटर से भी ज्यादा तेल इधर-उधर हो जाता है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से तैयार एक रिपोर्ट में ये आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट में माना गया है कि यदि केन्द्र की केरोसिन कैश सब्सिडी स्कीम प्रदेश में लागू कर दी जाए तो 60 फीसदी सब्सिडी बचाई जा सकती है। गौरतलब यह है कि जितना तेल राज्य को आंवटित होता है उतना पूरा उठ जाता है। *(रा.प., 13.03.12)*

अलवर में पकड़ी कारस्तानी

मामले की पोल अलवर के कोटकासिम में चलाए गए पायलट प्रोजेक्ट केन्द्र सरकार की केरोसिन कैश सब्सिडी ने खोली यहां से विभाग को पता चला कि वहां आधे से ज्यादा लोगों में केरोसिन की मांग ही नहीं है। पिछले तीन महीनों के आंकड़े यहां हुई कालाबाजारी के बड़े खेल की ओर इशारा करते हैं।

घटती जा रही विधान सभा की बैठकें

राजस्थान विधान सभा का सत्र लगातार छोटा होता जा रहा है। सरकार चाहे किसी भी दल की रही हो, वह सदन में बहस से बच रही है। हालत यह है कि राज्य की पहली विधान सभा में जहां करीब 60 बैठकें हुईं, तो वह आंकड़ा सिमट कर 28-29 बैठकों तक आ गया है।

पिछले दिनों हुए पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में भी बैठकों की घटती संख्या पर चिंता जताई गई थी। सम्मेलन में इस बारे में एक प्रस्ताव भी पारित कर केन्द्र सरकार को भी भेजा गया था। नियमों में प्रावधान है कि एक साल में सदन की कम से कम 60 बैठकें तो हों, लेकिन इसकी पालना नहीं होती न ही इसके लिए कोई कानून है।

विधान सभा अध्यक्ष दीपेन्द्र सिंह शेखावत स्वयं मानते हैं कि सदन की बैठकें कम होना अच्छी स्थिति नहीं है। सत्र में बैठकें कम होने से विधायकों को अपनी बात कहने का पूरा मौका नहीं मिलता। न तो वे अपने क्षेत्र की समस्या बता सकते हैं और न ही वे बजट या विधेयकों पर अपनी राय प्रकट कर पाते हैं। *(दै.भा., 05.03.12)*

खाद पर उठाई फर्जी सब्सिडी

उदयपुर में खेमली स्थित खाद कम्पनी धरमजी मोरारजी कैमिकल्स कम्पनी लि. से मध्यप्रदेश और राजस्थान की कम्पनियों को बेचे गए सिंगल-सुपर फॉस्फेट के नाम पर भारत सरकार से लाखों रुपए की फर्जी सब्सिडी उठाने का भंडाफोड़ हुआ है।

प्रारम्भिक छानबीन में सामने आया है कि कम्पनी ने 4000 टन फॉस्फेट कागजों में ही बेच दी और 900 रुपए प्रति टन के हिसाब से लगभग 36 लाख रुपए की सब्सिडी उठा ली। कृषि अयुक्तालय के संयुक्त निदेशक कृषि (आदान) ने मामले से सम्बन्धित सभी रिकॉर्ड और दस्तावेज मांगे हैं। इधर, उदयपुर जिला कलेक्टर ने प्रकरण की विस्तृत जांच के लिए इसे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को भेजने के आदेश दिए हैं। *(रा.प., 03.01.12)*

नालियों में बह गए 100 करोड़

गुलाबी नगर में हैरिटेज संरक्षण के नाम पर प्रापर्टी कनेक्शन योजना को मूर्तरूप देने से पहले राज्य सरकार के अनेक आला अफसरों ने अध्ययन करने के नाम पर यूरोपीय देशों का दौरा किया इसमें हवाई यात्राओं समेत लाखों रुपए खर्च किए गए।

इसके बाद 2008 में जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत आरयूडीआईपी व नगर निगम द्वारा करीब 100 करोड़ रुपए खर्च कर चार दीवारी के घरों के स्नानघर, रसोईघर आदि के गंदे पानी को सीवर लाइन से जोड़ने के लिए नालों में सीमेन्ट या कास्ट आइरन की ढलाई के मजबूत पाइप लगाने के बजाय हल्के प्लास्टिक के पाइप लगाकर इतिश्री कर दी गई।

अब ये पाइप गल चुके हैं और इनसे गंदा पानी गलियों में बह रहा है। पाइप लाइनों व चैम्बरों के संघारण के लिए ठेका भी दिया गया था, लेकिन 2009 से काम बन्द पड़ा है, गंदी गलियों की सफाई भी नहीं हो रही और करोड़ों रुपए नालियों में बर्बाद हो गए। *(रा.प., 25.01.12)*

कहां खर्च हो रहा है आदिवासियों का पैसा

पिछले पांच साल में सरकार दलितों और आदिवासियों के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित आधी राशि भी खर्च नहीं कर पाई। इससे उन्हें सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार योजनाओं में आबादी के अनुपात में धनराशि का प्रावधान कर देती है, लेकिन हकीकत यह है कि 50 फीसदी भी राशि खर्च नहीं हो रही।

आदिवासी लोग ज्यादातर गरीबी, बेरोजगारी और कुपोषण के शिकार है। नतीजतन कई गंभीर बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र की ओर से अनुसूचित जाति, जनजाति उपयोजना के संबंध में किए गए अध्ययन से कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।

(दै.भा., 13.03.12)

संसद में नहीं हुआ 258 घंटे काम

पिछले साल संसद के तीन सत्रों में सिर्फ 73 दिन कामकाज हुआ। इनमें निर्धारित 803 घंटों में से 258 घंटे कोई कामकाज नहीं हुआ। यानि करीब 30 से 35 फीसदी समय बर्बाद हो गया। यह समय महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए हंगामों की भेंट चढ़ गया।

पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के एक अध्ययन के अनुसार एक दिन में लोकसभा छह घंटे और राज्य सभा पांच घंटे काम करती है। इसका मतलब है कि निचले सदन में 438 घंटे और ऊपरी सदन में 365 घंटे कामकाज होना चाहिए था। लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः30 से 35 फीसदी समय बर्बाद हुआ। नतीजतन 97 महत्वपूर्ण विधेयक संसद में लंबित रह गए। वहीं सूचीबद्ध 1220 तारांकित प्रश्नों में से 139 का ही मौखिक जवाब दिया गया। राज्यसभा में भी 1240 में से 166 का ही जवाब मिला। 81 निजी विधेयक लोकसभा में पेश हुए इनमें से 4 पर ही चर्चा हो सकी। *(दै.भा., 02.01.12)*

करोड़ों के गलत भुगतान पर चुप्पी

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर शहरी कार्यालय में पिछले दो साल से चल रही विशेष जांच दल की आडिट में छात्रवृत्ति के नाम पर करीब 7 करोड़ रुपए से अधिक का अनियमित भुगतान करने का मामला सामने आया है। लेकिन विभाग के अधिकारी पिछले दो साल से कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति करने में जुटे हैं।

इस अवधि में सिर्फ 20 लाख रुपए से भी कम राशि की वसूली की गई है। आरटीआई में हुए इस खुलासे से विभाग अधिकारियों की कलई खुली तो वे अब ऑडिट टीम को असहयोग करने लगे हैं। विभाग के अफसर और कर्मचारियों ने मिलीभगत कर 7 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि उठाकर राजकोष को चपत लगाई है। यह घोटाला 10 करोड़ तक जाने की आशंका है।

(दै.भा., 12.03.12, 28.03.12)

भ्रष्टाचार करने वालों की खैर नहीं

महानरेगा में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए ऑल इण्डिया मनरेगा लेबर मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में हरपाल सिंह को राजस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने पिंकसिटी प्रेस क्लब में पत्रकारों को बताया कि ग्रामीण भारत के विकास से जुड़ी केंद्र सरकार की इस रोजगार गांरटी योजना में श्रमिकों की मजदूरी के नाम पर गबन व भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ, बिना किसी राजनैतिक दबाव के कमेटी सख्त प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई करेगी।

इसके लिए पहले 25 सदस्यीय प्रदेश स्तरीय कमेटियां इसके बाद जिला स्तर, तहसील स्तर और ब्लॉक स्तर पर कमेटियों का गठन किया जाएगा। कमेटी पूरे राज्य में 600 लोगों की नियुक्ति करेगी और उन्हें प्रशिक्षण देगी, जो कि अपने क्षेत्र में महानरेगा योजना के क्रियान्वयन पर नजर रखेंगी।

(पं.के., 29.03.12)

चुनाव में नहीं चलेगा काला धन

चुनावों में पारदर्शिता लाने और काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए लेखा परीक्षण और लेखांकन मानकों को अपनी मंजूरी दे दी है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इन मानकों और दिशा निर्देशों को तैयार किया है। आयोग और वित्तीय प्रवर्तन ऐजेंसियां जल्द ही मानकों और निर्देशों को अधिसूचित कर देंगी।

हाल ही हुए 5 राज्यों के चुनाव में आयोग की ओर से नियुक्त भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश में 36.17 करोड़, पंजाब में 12.13 करोड़, उत्तराखंड में 1.35 करोड़, गोवा में 60 लाख और मणिपुर में 47 लाख रुपए का काला धन जब्त किया था। इन हालातों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने इसे मंजूरी दी है।

(रा.प., 19.03.12)

अच्छे नम्बर देने के नाम पर रिश्वत

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रिटायर्ड प्रिंसिपल वीरेन्द्र कुमार गुप्ता को झुंझुनूं के गांव चनाना के बड़सरा की ढाणी स्थित आदर्श बाल निकेतन सी.सै. स्कूल में सीनियर सैकण्डरी रसायन विज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा लेने के लिए नियुक्त किया था। प्रायोगिक परीक्षा लेते समय उन्होंने संस्था के संचालक सुरेश कुमार से 36 छात्रों को अच्छे नम्बर देने की एवज में 36 हजार रुपए मांगे।

आखिर सौदा 18 हजार में तय होने पर सुरेश कुमार ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को मामले की जानकारी दी। वीरेन्द्र कुमार ने छात्रों से वसूले 18 हजार रुपए लेकर अपने बैग में रख लिए। इशारा पा कर ब्यूरो की टीम ने उसे गिरफ्तार कर बैग में रखे रुपए बरामद कर लिए। ब्यूरो टीम को बैग से इसके अलावा सीकर स्थित एक स्कूल की प्रायोगिक परीक्षा की कॉपियों के बंडल में 15 हजार रुपए और मिले। ब्यूरो का अनुमान है कि गुप्ता ने सीकर में भी छात्रों से रिश्वत ली है।

(रा.प. एवं दै.भा., 29.01.12)

भ्रष्टाचारियों की सम्पत्ति होगी जब्त

राज्य में भ्रष्ट अफसरों और कर्मचारियों की संपत्ति जब्त करने के लिए सरकार कानून लाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की है। इस बारे में पहले से मौजूद कानूनों का परीक्षण कराया जाएगा और जो बेहतरीन होंगे उन्हें लागू किया जाएगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि उड़ीसा या बिहार की तर्ज पर भ्रष्टाचारियों की सम्पत्तियां जब्त कर उन्हें सार्वजनिक काम में लिया जाए। जब्त सम्पत्तियों पर स्कूल, अस्पताल बने या उन्हें किसी अन्य सार्वजनिक काम में लिया जाए। कानून के इसी साल लागू होने की उम्मीद है।

(रा.प.एवं दै.भा., 03.02.12)

स्टाम्प पर लिखा अब रिश्वत नहीं लूंगा

भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के खिलाफ ग्रामीण स्तर पर लोग जागरूक हुए हैं। पिछले दिनों उदयपुर जिले की गोगुंदा तहसील इसकी मिसाल बना है। गोगुंदा तहसील के तिरोल सरपंच प्रताप सिंह के खिलाफ इन्दिरा आवास योजना के तहत गांव के कुछ लोगों से अवैध वसूली करने की बात सामने आई। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जिला कलेक्टर से की। इसके बाद कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए।

यह ही नहीं गांव वालों ने सरपंच पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए जब दबाव बनाया तो उसने जिनसे पैसा लिया था उन्हें वापस कर दिया। साथ ही सरपंच ने अवैध वसूली की बात को स्वीकार करते हुए स्टांप पर आगे कभी रिश्वत नहीं लेने का शपथ-पत्र भी लिख कर दिया। *(दै.भा., 09.02.12)*

रिश्वत का पैसा मिलेगा वापस

घूसखोरों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ट्रैप कार्रवाइयों में बतौर रिश्वत दी गई राशि अब शिकायतकर्ता को वापस मिल सकेगी। सरकार ने ब्यूरो के 'रिवाल्विंग फंड' के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। राज्य सरकार ने इस फंड के लिए ब्यूरो को 50 हजार रुपए दिए हैं। अदालत में शिकायतकर्ता के बयान होने एवं सामान्य प्रक्रिया पूरी करने के बाद ब्यूरो के मार्फत रिवाल्विंग फंड से यह राशि लौटाई जाएगी।

दूसरी ओर अदालत में बतौर सबूत जब्त की गई रिश्वत की राशि केस पूरा होने पर राजकोष में जमा होगी। अब तक भ्रष्टाचारी को पकड़वाने के बाद शिकायतकर्ता को रिश्वत में दी गई राशि के लिए केस में अदालत का फैसला आने तक लंबा इन्तजार करना पड़ता था। अदालत से भ्रष्टाचारी को सजा होने के बाद शिकायतकर्ता को यह राशि लौटाई जाती थी। *(रा.प., 06.03.12)*

देश में नेताओं का नैतिक पतन

आम आदमी को लग रहा है कि राजनीति के क्षेत्र में सबसे ज्यादा कमी चरित्र की ही है। इसलिए आजादी के बाद से अब तक न तो भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लग सका है और न ही नेताओं का नैतिक पतन का सिलसिला थमा है। उन पर मुकदमे भी चलते हैं, कुछ नेताओं को जेल भी जाना पड़ता है और पद भी गंवाने पड़ते हैं। लेकिन यह सिलसिला फिर भी थमने का नाम नहीं ले रहा। उनको न हया है और न ही शर्म।

भ्रष्टाचार के उदाहरणों को देखें तो लगता है कि राजनीति भ्रष्टाचारियों की आरामगाह बन गई है। जनता के खून-पसीने की कमाई के अरबों-खरबों रुपए इनके उदर में समाते जा रहे हैं। इन्हें यह भी फिक्र नहीं है कि हम जनता को क्या मुंह दिखाने लायक बचेंगे। *(रा.प., 10.02.12)*

इतना भ्रष्टाचार किसके लिए...

- *देश की अदालतों में 90 प्रतिशत भ्रष्टाचार के मामले नेताओं के खिलाफ चल रहे हैं*
- *ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुमान के अनुसार हर वर्ष 250 अरब रुपए रिश्वत का लेन देन होता है*
- *नौकरशाहों ने 92,122 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार के जरिए कमाए हैं*
- *वर्ष 2011 में 30 प्रतिशत सांसदों के खिलाफ फौजदारी मामले लंबित हैं। लोकसभा में 545 निर्वाचित सदस्य हैं*

भ्रष्टों के खिलाफ कोर्ट का अहम फैसला

मंत्रियों, सरकारी अफसरों-नौकरशाहों पर केस चलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने भ्रष्टाचार की शिकायत पर जांच का फैसला लेने के लिए 4 महीने की समय सीमा तय की है। अगर इस दौरान प्रधानमंत्री या सक्षम अधिकारी कोई फैसला नहीं ले पाते हैं, तो इसे जांच शुरू करने की मंजूरी माना जाएगा।

हालांकि कोर्ट ने संसद से अपील की है कि जांच की अनुमति न मिलने पर क्या हो, इसका फैसला संसद करे। वह इस बारे में समय सीमा तय करे। जरूरत पड़ने पर मौजूदा कानून में संशोधन कर नया कानून भी बनवाए। जस्टिस जीएस सिंघवी और जस्टिस एके गांगुली की बेंच ने डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अर्जी दाखिल करना हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट के इस फैसले से केन्द्र सरकार भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 19 में समय सीमा जोड़ने पर विचार कर सकती है। *(दै.भा., 01.02.12)*

फैसले का महत्व

- राजनीति के चलते जगह-जगह जांच नहीं अटकेगी।
- लोकसेवक के खिलाफ शिकायत का संवैधानिक अधिकार होने की पुष्टि।
- केन्द्र-राज्य नहीं लटका सकेंगे शिकायतें। तय समय में जांच का फैसला लेने का दवाब।

विगत तीन माह के दौरान रिश्वत लेते गिरफ्तार कुछ प्रकरणों की संक्षिप्त बानगियां

जिला	रिश्वत लेने वाले भ्रष्टाचारी का नाम	कार्यरत विभाग का नाम व पद	रिश्वत में ली राशि (रुपए में)	स्त्रोत
भरतपुर	जगत सिंह	ग्राम सेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत गंगोरा, भरतपुर	5,000	रा.प., 12.01.12
चूरू	रणवीरसिंह चौधरी नजीर खां	सहायक पुलिस उप निरीक्षक, भानीपुरा थाना, चूरू हवलदार, भानीपुरा थाना, चूरू	15,000	रा.प., 14.01.12
जोधपुर	नरेश बोथरा	वरिष्ठ अंकेक्षक (ऑडिट) एयरफोर्स स्टेशन, जोधपुर	1,000	रा.प., 15.01.12
भरतपुर	सुनिता सिंघल	महिला सुपरवाइजर, सीडीपीओ कार्यालय, सेवर	5,000	दै.भा.एवं रा.प., 19.01.12
जयपुर	देवेन्द्रपाल सिंह	डवलपमेंट ऑफीसर,खादी ग्रामोद्योग आयोग स्टेट इकाई	10,000	दै.भा.एवं रा.प., 21.01.12
चित्तौड़गढ़	दुर्गाशंकर शर्मा	थानाप्रभारी का जीप चालक, भैंसरोड़गढ़, चितौड़गढ़	3,500	रा.प., 22.01.12
राजसमन्द	मधुकान्ता शर्मा	सहायक परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, देवगढ़	2,000	रा.प., 24.01.12
जयपुर	संदीप कुमार जैन	एरिया सेल्स मेनेजर, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पो. लि.	20,000	दै.भा., 25.01.12
श्रीगंगानगर	जगराम मीणा	प्रबंधक, गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक,रामसिंहपुर शाखा	3,000	रा.प., 26.01.12
जयपुर	यादराम गुर्जर	सहायक उप निरीक्षक, बस्सी थाना, जयपुर	1,000	रा.प. एवं दै.भा., 01.02,12
नागौर	राम रतन जाट	पटवारी, भैरून्दा ग्राम पंचायत, नागौर	3,500	रा.प., 07.02.12
टोंक	प्रहलाद गुर्जर	कृषि पर्यवेक्षक, हथौना पंचायत, टोंक	1,000	रा.प., 07.02.12
श्रीगंगानगर	रणवीर सोनी राजेन्द्र विश्नोई	ग्रामसेवक, ग्राम पंचायत 8 पीएसडी, श्रीगंगानगर साथी कर्मचारी	2,000	रा.प., 11.02.12
झालावाड़	प्रेमपाल सिंह	सचिव, कुण्डीखेड़ा ग्राम पंचायत, झालावाड़	1,500	रा.प., 11.02.12
बीकानेर	रविन्द्र राय मेहता	पटवारी, भू-अभिलेखागार कार्यालय, बीकानेर	1,000	रा.प., 16.02.12
अलवर	माम चन्द भाग चन्द	उप निरीक्षक, तिजारा पुलिस, अलवर कांस्टेबल, तिजारा पुलिस, अलवर	10,000	रा.प., 22.02.12
बीकानेर	विश्वम्भर दयाल गुप्ता	कार्यवाहक डीजीएम, राज.स्टेट माइंस एण्ड मिनरल्स लि.	1,00,000	रा.प., 14.03.12
भीलवाड़ा	राजकुमार खेमचंदानी मदनगोपाल शर्मा	सहायक अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. कनिष्ठ अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि.	20,000	दै.भा., 21.03.12
सिरोही	रघुवीरदयाल मीणा	तहसीलदार, आबूरोड, सिरोही	5,000	रा.प. एवं दै.भा., 25.03.12
बीकानेर	भागीरथ आचार्य	ग्रामसेवक, रूनिया, बीकानेर	4,000	दै.भा., 25.03.12
चित्तौडगढ़	राम सिंह बंजारा	सरपंच, मोरवन ग्राम पंचायत, चित्तौड़गढ़	4,000	रा.प., 26.03.12
भीलवाड़ा	राधेश्याम स्वामी	तहसीलदार, बदनौर, भीलवाड़ा	10,000	दै.भा. एवं रा.प., 28.03.12
जयपुर	नारायणदास महेश्वरी	जेईएन, देवस्थान विभाग, उदयपुर	28,000	दै.भा. एवं रा.प., 30.03.12

देश में 70 फीसदी आबादी गरीब

केन्द्र सरकार ने देश में गरीबों की संख्या में कमी का दावा किया है। जबकि राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्य एन.सी.सक्सेना ने बताया कि सरकार का यह कहना कि गरीबी घटी है, सही नहीं है। योजना आयोग के आंकड़ों में तेंदुलकर समिति को आधार मानते हुए गरीबों की संख्या 37.5 करोड़ बताई थी। उन्होंने कहा कि गरीबी के बहुमुखी मूल्यांकन की जरूरत है, क्योंकि वास्तविकता यह है कि देश में अभी भी 70 फीसदी आबादी गरीब है।

उन्होंने बताया कि गरीबी से संबंधित सरकार के अनुमानों में कई खामियां है, उनमें पोषक आहार, स्वच्छता, पेयजल, स्वास्थ्य सेवा और शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता जैसे कारकों का ध्यान नहीं रखा गया है। राष्ट्रीय सैम्पल सर्वे के आंकड़े गलत है। सरकार को इन अनुमानों पर आलोचना का शिकार होना पड़ा है। सलाहकार समिति सरकार को नीतिगत सलाह देती है। *(रा.प., 26.03.12)*

सरपंच देंगे योजनाओं की जानकारी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई बार कहा है कि सरकार की ज्यादातर लोक कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी जमीनी स्तर तक नहीं पहुंचती। इससे उन योजनाओं के लाभ आम लोगों को नहीं मिलते। केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जमीनी स्तर पर हकीकत जानने के लिए मुख्यमंत्री ने अब नया तरीका निकाला है।

अब सरपंचों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से योजनाओं की वास्तिविक स्थिति और उन पर हो रहे अमल व उनसे लोगों को मिल रहे लाभों के बारे में जानकारी फोन पर ली जा रही है। इस काम के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में एक दर्जन से भी ज्यादा अफसर और कर्मचारी लगाए गए हैं। वे रोजाना फोन कर पंचायत स्तर से इस बारे में पूरी जानकारी (फीड बैक) जुटा कर मुख्यमंत्री को दे रहे हैं।

(दै.भा., 06.1.12)

खाद्य सुरक्षा एक कानूनी हक

केन्द्र सरकार ने सभी लक्षित लोगों, विशेषकर गरीब और दुर्बल वर्गों के लिए भोजन को एक कानूनी हक बनाते हुए पूरे परिवार स्तर पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय किए हैं। इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 संसदीय समिति के समक्ष है।

इस विधेयक के उद्देश्यों को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने के लिए यूआईडी-'आधार' प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। इसके तहत एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण के लिए राष्ट्रीय सूचना उपयोगिता केन्द्र सृजित किया गया है। लोगों तक नकद सब्सीडी, विधवा, निशक्तता पेंशन व छात्रवृति आदि के भुगतान में इस प्रणाली का उपयोग होगा और लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे राशि जमा हो सके ऐसी व्यवस्था की जाएगी।

(रा.प. एवं दै.भा., 17.03.12)

पंचायतों का होगा सामाजिक अंकेक्षण

देश में पहली बार पंचायतों का विशेष सामाजिक अंकेक्षण कराने का काम बाड़मेर जिले की शिव पंचायत से शुरू होने जा रहा है। जल्द ही हैदराबाद से एक प्रशिक्षित जांच टीम यहां पहुंचेगी। पायलट प्रोजेक्ट के लिए देश भर से चयनित लोगों को हैदराबाद में विशेषतौर पर प्रशिक्षण दिया गया है।

टीम में लेखा व तकनीकी के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं। शिव पंचायत समिति की 47 ग्राम पंचायतों में जांच का काम डेढ़ माह में पूरा होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि इस विशेष जांच में कई अनियमितताएं सामने आएगी। बाद में जांच रिपोर्ट को ग्राम सभा में भी रखा जाएगा। ग्रामीण ग्राम सभा में किसी भी तरह की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। *(रा.प., 15.01.12)*

किसानों व खेती-बाडी को खास तबज्जो

केन्द्रीय बजट में वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र को प्राथमिक दर्जा दिया है। खेती में तकनीकी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत की गई है। इसके लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए नई प्रौद्योगिकी अपनाने पर जोर दिया जाएगा।

कृषि उपकरणों, उनके पुर्जों और उर्वरक परियोजनाओं के विस्तार व स्थापना के लिए बुनियादी सीमा शुल्क को कम किया गया है। किसानों को फसलों के लिए सही समय पर कर्ज मिल सके ऐसी व्यवस्था की जाएगी।

समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 4 फीसदी पर कर्ज की योजना को बरकरार रखा गया है। कृषि उत्पादों के सही भंडारण के लिए उन्हें फसल के बाद के ऋणों पर 3 प्रतिशत ब्याज की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। कृषि का बजट 18 फीसदी बढ़ाकर 20 हजार 208 करोड़ रुपए किया गया है, जिससे किसानों के लिए कई नई राहें खुलेंगी। किसान कार्ड अब स्मार्ट कार्ड में बदले जाएंगे जिनका एटीएम में भी उपयोग किया जा सकेगा। *(रा.प. एवं दै.भा., 17.03.12)*

आधार का दायरा बढ़ाया

सरकार ने यूआईडी कार्ड 'आधार' के दायरे को तीन गुना बढ़ाते हुए इसकी पहुंच देश की आधी आबादी तक करने का फैसला किया है।

गृहमंत्री पी चिदंबरम ने यूआईडी प्राधिकरण के प्रमुख नंदन नीलकेणि व योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया की मौजूदगी में कहा कि आधार का दायरा 20करोड़ से बढ़ाकर 60 करोड़ किया गया है। बायोमेट्रिक आंकड़े एकत्र करने में दोहराव की गुंजाइश खत्म करते हुए तय किया गया है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर व यूआईडी तैयार करने के लिए दो बार आंकड़े नहीं लिए जाएंगे। *(रा.प., 28.01.12)*

वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनेगी परिषद

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जल्द ही वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक परिषद का गठन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मुकुल वासनिक इस परिषद के अध्यक्ष होंगे। बयान के मुताबिक यह परिषद वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण तथा उनके जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के मुद्दों पर नजर रखेंगी ताकि वे अपना बेहतर जीवन निर्वाह कर सके। *(न.नु., 02.02.12)*

योजना आयोग ने भर दी झोली

योजना आयोग ने राजस्थान की झोली भर दी है। आयोग ने राज्य की वर्ष 2012-13 की वार्षिक योजना का आकार 33,500 करोड़ रुपए तय किया है। ये राशि चालू वित्तीय वर्ष की वार्षिक योजना से 6000 करोड़ यानि 21.82 फीसदी ज्यादा है। सिर्फ इतना ही नहीं 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) में राज्य के लिए एक लाख 94 हजार 283 करोड़ 44 लाख रुपए की योजना राशि तय की गई है।

योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में पहुंचे आला अधिकारियों में विचार के बाद वार्षिक और पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतिम रूप दिया गया। इस अवसर पर योजना आयोग ने राजस्थान की तारीफ की है कि पूरे देश में सबसे पहले उसकी वार्षिक योजना और पंचवर्षीय योजना मंजूर हुई है। *(न.नु एवं रा.प., 22.03.12)*

घाटे में हैं प्रदेश की बिजली कंपनियां

प्रदेश की अजमेर, जयपुर और जोधपुर डिस्कॉम यानि तीनों बिजली कंपनियां मौजूदा समय में करीब 40 हजार करोड़ रुपए के घाटे में हैं। इससे कई योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। तीनों ही बिजली कम्पनियां मौजूदा समय में काफी आर्थिक संकट में हैं। यह बात डिस्कॉम के अध्यक्ष सुधांशु पंत ने अजमेर में पत्रकारों से कही।

उन्होंने कहा कि पिछले तीन माह पहले तो स्थिति और भी खराब थी। बैंकों ने ऋण देने से इन्कार कर दिया, बिजली संबंधित योजनाओं के लिए सामान तक नहीं खरीदा जा रहा था। मगर अब आर्थिक स्थिति में मामूली सुधार हुआ है। सरकार की ओर से मिली मदद और बैंकों द्वारा ऋण किश्तों में दी गई थोड़ी राहत से कुछ सुधार हुआ है। आर्थिक स्थिति से उबरने के लिए इंजीनियरों को बकाया वसूली करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

(दै.भा., 08.02.12)

खम्भे से मीटर तक केबल किसका?

ज्यदातर लोगों को यह जानकारी नहीं है कि बिजली का नया कनेक्शन लेने पर बिजली के खम्भे से मीटर तक केबल डालने की जिम्मेदारी डिस्कॉम की होती है। इसका फायदा बिजली कंपनियों के अभियंता उठा रहे हैं। देखा जा रहा है कि बिजली कर्मचारी मीटर तक लाइन तभी खींचते हैं जब तक उपभोक्ता बाजार से केबल खरीद कर नहीं लाते। जबकि कनेक्शन के लिए केबल डिस्कॉम द्वारा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। डिस्कॉम के कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी उपभोक्ता के सिर मढ़कर उसकी जेब हल्की कर रहे हैं।

इस मनमानी को लेकर कई उपभोक्ता जानते हुए भी सवाल नहीं उठाते, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं कनेक्शन न फंस जाए। जयपुर डिस्कॉम के मुख्य अभियंता ए.के.कल्ला का कहना है कि नियमानुसार सर्विस लाइन देने की जिम्मेदारी डिस्कॉम की ही है। ऐसा कोई मामला सामने आता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। *(रा.प., 15.01.12)*

सरकारी विभागों से नहीं हो रही वसूली

करोड़ों के घाटे से जूझ रहे बिजली कम्पनियों के अफसरों ने वित्तीय वर्ष में शत प्रतिशत राजस्व वसूली के निर्देश दिए हैं। जबकि वित्तीय वर्ष समाप्ति पर है और अभी भी सरकारी महकमों पर दस करोड़ से भी ज्यादा का बकाया है।

अभियंताओं का कहना है कि इस पैसे की वसूली के लिए कोई कार्रवाई करते हैं तो हंगामा खड़ा हो जाता है और नहीं करने पर उन्हें खुद पर कार्रवाई का डर लगा रहता है। ऐसे में सामान्य उपभोक्ताओं के हजार दो हजार के बकाया बिल पर तुरन्त कनेक्शन काट रहे अभियंता असमंजस में है कि आखिर इस सरकारी पैसों की वसूली कैसे करे। पिछले दिनों सरकारी महकमों पर भी कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू की गई, लेकिन हंगामा होने पर फिर से अभियंताओं को बैक फुट पर आना पड़ा।

(रा.प., 26.03.12)

बिजली पर दिया सर्वाधिक ध्यान

प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि विद्युत क्षेत्र में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1790 मेगावाट लक्ष्य के विरुद्ध 1830 मेगावाट क्षमता की अतिरिक्त वृद्धि अर्जित की गई है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए भी राज्य सरकार ने ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बनाया है।

इस योजना अवधि के लिए राज्य क्षेत्र में 7750 मेगावाट और निजी क्षेत्र में 3840 मेगावाट क्षमता की विद्युत उत्पादन परियोजनाओं पर काम शुरू किए गए हैं। राज्य में पहली बार 2 गुणा 660 मेगावाट क्षमता के 6 सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित तापीय विद्युत गृहों की सूरतगढ़, छबड़ा, कालीसिंध और बांसवाड़ा में स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। *(न.नु., 22.03.12*

सौर ऊर्जा आवंटन में प्रदेश सबसे आगे

ऊर्जा मंत्री डॉ.जितेन्द्र सिंह ने बताया कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसे जवाहर लाल नेहरू सौर ऊर्जा मिशन से 1100 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन में से 944 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य मिला है।

उन्होंने बताया कि राज्य में सौर ऊर्जा नीति के तहत सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयासों को निवेशकों ने सराहा है। यही कारण है कि भूमि बैंक के जरिए भू आंवटन के लिए 700 निवेशक आगे आए हैं और 1650 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए अपना पंजीयन कराया है। उन्होंने बताया कि जैसलमेर और जोधपुर में सौर ऊर्जा उत्पादन की असीमित संभावनाएं हैं। *(न.नु., 03.03.12)*

दूधिया रोशनी का ख्वाब अधूरा

जयपुर डिस्कॉम ने तीन साल पहले केन्द्रीय प्रोजेक्ट के जरिए जनता को दूधिया रोशनी का सपना दिखाया था। योजना के तहत उपभोक्ताओं को एक वल्ब और 15 रुपए के बदले दो सीएफएल दिए जाने थे।

इस योजना के पीछे मूल उद्देश्य कार्बन क्रेडिट कमाना था। लेकिन इस काम में डिस्कॉम ऐसा पिछड़ा कि योजना ठंडे बस्ते में चली गई। डिस्कॉम ने जिस निजी कम्पनी को योजना का जिम्मा छोड़ा था वो अब तक कार्बन क्रेडिट के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवा पाई।

जयपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता के.के.पुरोहित का कहना है कि इस योजना पर काम चल रहा है और कम्पनी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए प्रयासरत है। जैसे ही यह काम हो जाएगा सीएफएल बांटना शुरू कर देंगे। *(रा.प., 30.01.12)*

उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनना जरूरी

उपभोक्ताओं की बात सुने बिना बिजली कनेक्शन विच्छेद करने वाले अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। सिटी सर्किल के अधीक्षण अभियंता अर्जुन सिंह ने अभियंताओं को यह निर्देश दिया है कि किसी उपभोक्ता ने बिजली बिल का पैसा जमा करा दिया हो और विभाग के खाते में पैसा नहीं पहुंचा हो तो पहले पूरी सुनवाई करे फिर कनेक्शन काटे जाएं।

बिजली बिल की राशि ई-मित्र के माध्यम से जमा कराने के बावजूद बिजली कनेक्शन विच्छेद करने की शिकायतें सामने आने और मीडिया में इस बाबत समाचार छपने के बाद उक्त निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानी नहीं हो यह ध्यान रखना होगा। *(रा.प., 21.02.12, 22.02.12)*

बढ़ेगा बिजली कनेक्शन और मीटर शुल्क

अप्रेल में बिजली की दरें बढ़ने के साथ आपको निगम एक और झटका देने वाला है। बिजली कनेक्शन लेने, मीटर खराब होने पर उसकी जांच कराने और कटे हुए कनेक्शन को जुड़वाने पर उपभोक्ता को वर्तमान दर से 25 फीसदी ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा।

बिजली निगम ने विद्युत आपूर्ति की सेवा शर्तें 25 फीसदी महंगी करने की तैयारी कर ली है। बिजली निगम के तकनीकी निदेशक बीएल माहेश्वरी ने बताया कि इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग को भिजवाया गया है।

(दै.भा., 13.03.12)

खोदा बोरवेल तो होगी दो साल की सजा

बिना मंजूरी नलकूप, कुआं या बोरवेल खुदवाकर भूजल का अंधाधुंध दोहन करने वालों को दो साल की सजा और दो हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। पानी की कमी वाले इलाकों में भूजल दोहन रोकने के लिए लाए जा रहे कानून में ऐसे प्रावधान किए जा रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से तैयार विधेयक के मसौदे में यह खुलासा किया गया है।

सरकार ने हाईकोर्ट में बताया कि पेयजल स्त्रोतों के संरक्षण के लिए जल्द ही विधेयक लाया जा रहा है। पेयजल स्त्रोतों के संरक्षण के इस विधेयक में जिला कलेक्टर को भूजल के अतिदोहन वाले इलाके घोषित करने का अधिकार होगा। इन क्षेत्रों से बिना मंजूरी के कोई भी भूजल नहीं निकाल सकेगा।

(रा.प., 08.01.12)

नदियों को जोड़ने का काम शुरू हो

देश की नदियों को आपस में जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना अब मूर्त रूप ले सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह परियोजना को समयबद्ध तरीके से लागू करे। कोर्ट ने केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री के नेतृत्व में एक उच्चाधिकार समिति गठित की है, जो परियोजना का प्रारूप तैयार करेगी।

नदी जोड़ो परियोजना 2002 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने बनाई थी। यदि इस परियोजना पर जल्द काम शुरू होता है तो वे क्षेत्र जो हर साल कम वर्षा और उससे सूखे का सामना करते हैं वहां के लोगों के लिए फायदेबंद साबित होंगे। इससे केन्द्र की ओर से चिन्हित 14 लिंक में से राजस्थान को यमुना-राजस्थान और राजस्थान-साबरमती लिंक से फायदा मिलेगा। *(रा.प. एवं दै.भा., 28.02.12)*

बदले जाएंगे पानी के खराब मीटर

जयपुर शहर में जलदाय विभाग के करीब साढे तीन लाख उपभोक्ता है। इनमें से करीब डेढ़ लाख उपभोक्ताओं के पानी के मीटर खराब होने से बन्द पड़े हैं। ऐसे में इन उपभोक्ताओं को औसत बिल जारी किए जाते हैं। इससे उपभोक्ता और जलदाय विभाग दोनों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री जितेन्द्र सिंह ने शहर में बन्द पड़े मीटरों को लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों की खिंचाई की है। विभाग अब बन्द पड़े इन मीटरों की सुध लेगा और अपने स्तर पर इन्हें बदलने का काम करेगा।

(रा.प., 14.01.12)

अतिदोहन से गिरा भूजल स्तर

पिछले एक साल में जयपुर के भूजल स्तर में दो मीटर से भी ज्यादा की कमी आई है। अतिदोहन के चलते यह ही नहीं बल्कि पानी की क्वालिटी भी गिरी है। पानी में लवण और क्षार की मात्रा में बढ़ोतरी दर्ज की है वहीं नाइट्रेट, फ्लोराइड़ सहित अन्य रसायन भी मापदंडों से ज्यादा हो गए हैं। शहर को बीसलपुर योजना से मिल रहे एक तिहाई पानी के बावजूद भूजल स्तर में यह गिरावट चिंताजनक है।

शहर में रोजाना 3800 लाख लीटर पानी मिल रहा है। जिसमें से 2600 लाख लीटर बीसलपुर योजना से तथा 1200 लाख लीटर पानी ट्यूबवेलों से दोहित हो रहा है। इसके अलावा करीब 5 हजार प्राईवेट ट्यूबवेलों से रोजाना 2500 लाख लीटर पानी भूजल स्तर से निकाला जा रहा है, जिस पर कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसे में पानी रिचार्ज कम हो रहा है और दोहन ज्यादा हो रहा है। हर बिल्डिंग में रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने पर ही स्थिति सुधर सकती है। *(दै.भा., 22.03.12)*

मल्टीस्टोरीज में जल कनेक्शन

सरकारी जलापूर्ति से अब तक महरूम रही बहु मंजिला इमारतों में जलदाय विभाग की ओर से केवल एक की कनेक्शन दिया जाएगा। फ्लैटधारी भूमिगत टेंक बनाकर उसमें विभाग की ओर से आपूर्ति किए जाने वाले पानी का भंडारण कर उपयोग कर सकेंगे। महुमंजिला इमारतों के लिए अधिक व्यास वाली उपभोक्ता लाइन का प्रयोग किया जाएगा। वर्तमान में इन इमारतों में ट्यूबवेल सूखने और भूजल स्तर गिरने से पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

इन भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था होना जरूरी होगा। इसके अलावा गार्डन की सिंचाई में पेयजल का इस्तेमाल नहीं होगा केवल रिसाइकिल जल ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह फैसला यूडीएच और पीएचईडी के आला अफसरों की बैठक में विस्तार से चर्चा के बाद लिया गया है।

(रा.प.एवं दै.भा., 14.01.12)

बढ़ते घर और बुझती प्यास

गिरते भूजल स्तर और कम होती बारिश के बीच प्रदेश में दूर से पानी लाकर प्यास बुझाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वर्तमान में हालात यह है कि प्रदेश में एक चौथाई से ज्यादा परिवार आधा किलोमीटर या उससे भी अधिक दूरी से पानी लाकर गुजारा करते हैं। गिरते भूजल स्तर के कारण अब कुओं का आसरा भी नजर नहीं आ रहा। हैण्डपम्प भी साल दो साल में दम तोड़ रहे है। इससे पानी पर सरकार का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है।

दूर दराज से पानी लाने वाले परिवारों की संख्या जो दस साल पहले तक 23.8 फीसदी थी, 2011 की जनगणना में 25.9 फीसदी पहुंच गई है। जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक 31.9 फीसदी परिवारों के लिए आधा किलोमीटर तक के दायरे में पानी का साधन नहीं है। पिछले 10 साल में यह संख्या घटने के बजाय साढ़े तीन फीसदी बढ़ी है।

(रा.प., 22.03.12)

नहीं बढ़ाई जाएंगी पानी की दरें

जयपुर शहर के 30 फीसदी क्षेत्र में 24 घंटे पानी सप्लाई मई 2012 के अंत तक शुरू हो जाएगी। इसमें चारदीवारी क्षेत्र भी शामिल होगा। इसके लिए सर्वे का काम तेजी से हो रहा है और पाइप लाइनें भी बदली जा रही हैं।

यह जानकारी पीएचईडी के मुख्य अभियंता (मुख्यालय) अनिल भार्गव ने देते हुए बताया कि 24 घंटे सप्लाई के बाद भी पानी की दरें नहीं बढ़ाई जाएगी। उपभोक्ताओं के घरों में बदले जाने वाले मीटरों का खर्च भी सरकार वहन करेगी। अभी एक लाख मीटर बदलने की योजना है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत अभी चार स्थानों पर 24 घंटे पानी दिया जा रहा है, उनमें सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इनमें 8000 कनेक्शन है। *(दै.भा., 17.02.12)*

गांव में होगा घर-घर पानी कनेक्शन

जलदाय विभाग ने सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल कनेक्शन देने के नियमों में बदलाव करने का प्रस्ताव भेजा है। विभाग की ओर से तैयार प्रस्ताव के अनुसार जिन क्षेत्रों में पेयजल पूरी मात्रा में उपलब्ध है वहां के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को घरों में पानी के कनेक्शन दिए जाएंगे। चाहे वहां की आबादी कम ही क्यों न हो? इससे गांवों के लाखों परिवारों को फायदा मिलेगा। अभी 4000 से अधिक आबादी वाले गांवों के घरों में पानी कनेक्शन देने का नियम है । विभाग ने इसमें शिथिलता बरतने की सिफारिश की है । *(रा.प., 01.02.12)*

महिला सशक्तिकरण पर जोर

महिला स्वयं सहायता समूह सामाजिक और आर्थिक उत्थान में काफी मददगार साबित हुए हैं। केन्द्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने लोक सभा में बजट पेश करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि इसे देखते हुए केन्द्र सरकार ने पिछले बजट में महिला स्व-सहायता समूह विकास निधि का सृजन किया था। इस निधि को बढ़ाकर अब 300 करोड़ रुपया कर दिया गया है।

समूहों को सात प्रतिशत सालाना दर से तीन लाख रुपए तक के ऋण के रूप में आर्थिक सहायता मिल सकेगी। समय पर ऋण चुकाने पर तीन फीसदी ब्याज माफ हो जाएगा। इस ऋण से समूह की महिलाएं कोई व्यवसाय खोल कर आत्मनिर्भर हो सकेंगी।

(रा.प. एवं दैभा.17.03.2012)

महिला सुरक्षा के लिए कानून में संशोधन

महिलाओं पर तेजाब फेंकना अब अलग अपराध की श्रेणी में शामिल हो सकता है। इसके लिए केन्द्र सरकार भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में गृह मंत्रालय की उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव के अनुसार महिला पर तेजाब फेंकने पर कम से कम 10 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकेगा।

एक अन्य प्रस्तावित संशोधन के अनुसार 16 साल से कम उम्र की लड़की से शारीरिक संबंध बनाने पर उसे दुष्कर्म माना जाएगा। वर्तमान में यह उम्र 15 साल है। अब इस संशोधन के बाद 16 साल से कम उम्र की पत्नी से भी शारीरिक संबंध बनाना दुष्कर्म की श्रेणी में माना जाएगा।

(दै.भा., 16.02.12)

विधानसभा में दबी है इनकी आवाज

राजस्थान में महिलाओं की आबादी भले ही 48-49 प्रतिशत है, लेकिन विधानसभा में इन तीन सालों में इनकी भागीदारी कोई अच्छी नहीं रही। वे 200 सीटों में से 28 पर ही अपनी उपस्थिति दर्ज करवा पाई हैं। इसके बावजूद उन्हें विधानसभा में बोलने के पर्याप्त मौके नहीं मिलते। ज्यादातर महिलाएं पहली बार विधायक बनी हैं, इसलिए कुछ तो वे खुद बोलने से कतराती हैं और कुछ मौकों पर पुरुष विधायक भी उन्हें प्रोत्साहित नहीं करते।

हालांकि विधायकों का मानना है कि सदन में ऐसा माहौल बने, जिससे महिलाओं को अपनी बात कहने का मौका मिल सके। क्योंकि उनकी आवाज आधी आबादी की आवाज है। पुरुष विधायकों को उन्हें बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

(रा.प., 13.03.12)

जिम्मेदारी का काम महनताना चुटकी भर..!

राजस्थान में लाखों ऐसे कर्मचारी है जो काम तो सरकारी विभागों में करते हैं लेकिन उन्हें इसके बदले महनताना चुटकी भर ही मिलता है। हर साल केन्द्र व राज्य का बजट जारी होता है, लेकिन इन कार्मिकों की हालत जस की तस है। इन कर्मचारियों के हाथों में लोगों का स्वास्थ्य और बच्चों का पोषण जैसे काम दिए हुए हैं।

मसलन ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत आशा सहयोगिनों को 1000 रुपए मासिक, आंगनबाड़ियों में कार्यरत कार्यकर्ता को 3000 व सहायक को 1500 रुपए मासिक, स्कूलों में मिड-डे-मील के तहत खाना बनाने वाले कुक-कम हैल्परों को 1000 रुपए मासिक मिलते है। इनसे रोजाना 8 से 12 घंटे तक काम तो लिया जाता है पर इन्हें अन्य सुविधाएं और न्यूनतम मजदूरी भी नसीब नहीं है।

राज्य के पूर्व मुख्य सचिव एम.एल. मेहता का कहना है कि अगर सरकार पूरा काम लेती है तो वेतन भी पूरा देना चाहिए। *(रा.प., 26.03.12)*

नए साल के बजट में याद आई स्कूटी

राज्य विधान सभा में हाल ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए साल का बजट रखा तो अफसरों को देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना याद आई। पिछले साल के बजट में पिछड़ी जातियों के लिए एक विशेष पैकेज के रूप में बेटियों के लिए यह योजना घोषित की थी।

योजना का मकसद था कि नए सत्र से राज्य की 500 बेटियां अपनी स्कूटी से कॉलेज जाएं। लेकिन पूरा साल बीत गया छात्राओं को स्कूटी नहीं मिली। अब जाकर विभाग अपने स्तर पर तेजी से कोशिश कर रहा है कि माह मार्च से पहले छात्राओं को 500 स्कूटी वितरित हो सके।

(दै.भा., 02.03.12 एवं रा.प., 11.03.12)

देश में 42 फीसदी बच्चे कुपोषित

हमारे देश में 16 करोड़ बच्चे हैं। इनमें से 42 फीसदी बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। इसका खुलासा हाल ही नांदी फांउडेशन और सिटीजन्स एलायंस अगेंस्ट मेलन्यूट्रिशन द्वारा किए गए 'हंगामा'(भूख और कुपोषण) नामक एक सर्वे रिपोर्ट से हुआ है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस रिपोर्ट को जारी करते हुए इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के कुपोषण को राष्ट्रीय शर्म बताया है।

इसके एक माह बाद ही दूसरी शर्मसार करने वाली एक खबर और आ गई। अंतरराष्ट्रीय संस्था यूनीसेफ ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि नवजातों की मृत्यु दर के मामले में भारत सबसे खराब 50 देशों में शामिल है। पांच साल से कम उम्र के शिशु मृत्यु दर में भारत की रैंकिंग 46 आंकी गई है। भारत में बच्चों के मरने की संख्या ही ऊंची नहीं बल्कि यहा पैदा होने के बाद उनके जिंदा रहने की संभावना एक चुनौति है। यहा हर साल पैदा होने वाले 2.71 करोड़ बच्चों में से करीब 28 फीसदी बच्चों का वजन सामान्य से कम पाया गया है। *(दै.भा., 11.01.12, 01.03.12)*

24 फीसदी बच्चे भूखे रह जाते हैं

भारत में करीब 30 फीसदी परिवारों को बढ़ती महंगाई के कारण अपने भोजन में कटौती करनी पड़ रही है, जबकि करीब 25 फीसदी बच्चे रोज भूखे रह जाते हैं।

'सेव द चिल्ड्रन' जो कि एक गैर सरकारी संस्था है ने खाद्य मंहगाई और खान-पान की आदतों पर व इसके असर पर पांच देशों में सर्वेक्षण किया है।

संस्था की सीईओ जैसमिन ह्विटब्रेड ने कहा कि यह अचंभित करने वाला है कि 66 फीसदी अभिभावक कह रहे हैं कि ऊंची कीमत के कारण वह बच्चों के खाने के पदार्थ नहीं खरीद पाते हैं। 17 फीसदी तो यहां तक कह रहे हैं कि उनके बच्चे स्कूल छोड़ कर काम पर गए हैं। यह बच्चों के लिए खतरनाक है। सर्वेक्षण दिसम्बर और जनवरी में नाइजीरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पेरू और भारत में किया गया। इन पांच देशों को चुनने का कारण यह बताया गया कि दुनिया के आधे से ज्यादा कुपोषित बच्चे इन देशों में रहते हैं। *(न.नु., 16.02.12)*

दूरसंचार सेवाएं

टेलीकॉम कंपनियों ने दी सेवाओं की जानकारी

टेलीकॉम रेगूलेटरी अथोरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) के सहयोग से 31 जनवरी 2012 को चूरू जिले में कट्स एवं दीनबन्धु सेवाश्रम, चूरू तथा 18 फरवरी2012 को सामाजिक विकास समिति,धौलपुर के सयुंक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय टेलीकॉम कंज्यूमर ऐजुकेशन कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में कट्स के धर्मेन्द्र चतुर्वेदी द्वारा ट्राई के द्वारा प्रायोजित कार्यशालाओं के उद्देश्य और कार्यप्रणाली की विस्त्रत जानकारी दी गई तथा कट्स प्रतिनिधि अर्जुनकान्त झा ने उपभोक्ताओं के हित में ट्राई द्वारा जारी नियमावली का प्रस्तुतिकरण किया। इन कार्यशालाओं में विभिन्न टेलीकॉम व मोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद थे और उन्होंने अपनी सेवाओं से प्रतिभागियों को अवगत कराया।

इस अवधि में दौसा जिले में 01 मार्च 2012 को तीसरी कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में कट्स के दीपक सक्सेना ने ट्राई और उपभोक्ताओं के अधिकारों की जानकारी देते हुए अत्यधिक जागरूक और सजग रहने की जरूरत पर बल दिया तथा धर्मेंद्र चतुर्वेदी ने ट्राई द्वारा जारी नियमावली का प्रस्तुतिकरण किया। कार्यशाला का संचालन के.बी. मेमोरियल सोशियल वैलफेयर सोसायटी के सचिव कमलेश बोहरा ने करते हुए कहा कि मोबाइल कंपनियों को उपभोक्ताओं के हितों के बारे में भी सोचना चाहिए। कार्यशाला में भारत दूरसंचार निगम लि. के डीईटी एल.एन. मीणा तथा एईएन आर.एम. शर्मा सहित विभिन्न टेलीकॉम व मोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद थे। सभी ने अपनी-अपनी सेवाओं की जानकारी देते हुए उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान किया।

निवेशक शिक्षा

सार्वजनिक निर्गम प्रक्रिया बदलेगा सेबी

देश में पूंजी बाजारों में अधिक पूंजी आकर्षित करने व निवेशक सेंटीमेंट में सुधार के मद्देनजर शेयर बाजार नियामक आयोग एजेंसी 'सेबी' कई कदम उठाने की योजना बना रहा है। इसमें सार्वजनिक निर्गम जारी करने की वर्तमान प्रक्रियाओं में भी बड़ा फेरबदल किए जाने की प्रबल संभावना है।

सेबी अध्यक्ष यू.के.सिन्हा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि एजेंसी निवेश की पूरी प्रक्रिया को ही आसान बनाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि सेबी पूंजी बाजारों में रिफॉर्म की प्रक्रिया में गति लाने के लिए प्रयासरत है, इसलिए नई योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाएगी। पिछले दिनों सेबी ने रिटेल निवेशकों के लिए एक ही बार केवाईसी पंजीकरण की व्यवस्था को मंजूरी दी है जिसके तहत निवेशक अब आसानी से शेयरों व म्यूचुअल फंडों में निवेश कर सकेगें। *(न.नु., 26.01.12)*

वित्तीय सेवाएं

बचत खाता संख्या बदले बिना बदल सकेंगे बैंक

वित्त मंत्रालय बैंक ग्राहकों को अपने बचत बैंक खाता संख्या दूसरे बैंकों में स्थानान्तरित करने की अनुमति देने की संभावना तलाश रहा है। इससे ग्राहक बगैर बचत खाता संख्या बदले कोई भी बैंक बदल सकेंगे। पिछले साल रिजर्व बैंक ने बचत खाता जमाओं पर ब्याज दरों को नियंत्रणमुक्त कर दिया, जिसके बाद कुछ निजी बैकों ने बचत बैंक जमाओं पर ब्याज दर बढ़ाकर 7 प्रतिशत तक कर दी। बैंक बदलने की ऐसी सुविधा से ग्राहक अपने खाते को ज्यादा ब्याज देने वाले बैंक में स्थानान्तरित कर सकेंगे। इस बारे में रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों से विचार विमर्श शुरू कर दिया गया है।

वित्तीय सेवाओं के सचिव डी.के.मित्तल ने यह जानकारी देते हुए कहा कि 'हम बचत खाता संख्या पोर्टेबिलिटी को लागू करना चाहते हैं। अभी कुछ तकनीकी समस्याएं हैं जिनकी पहचान की गई है और इन्हें जल्द ही हल कर लिया जाएगा। *(दै.भा.एवं न.नु. , 04.01.12)*

सड़क सुरक्षा

ट्रैफिक नियम तोड़ा तो जुर्माना पांच गुना

सड़क पर चलने के नियम तोड़ने वालों को पहले से पांच गुना ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने, निर्धारित गति से तेज गाड़ी चलाने, बिना हैलमेट के दोपहिया वाहन चलाने, बिना सीट बेल्ट बांधे चार पहिया गाड़ी चलाने वालों को न सिर्फ ज्यादा जुर्माना देना होगा बल्कि जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। इसके लिए केन्द्रीय कैबिनेट ने मोटर वाहन कानून में संशोधनों को मंजूरी दे दी है। इसे अब इसी संसद सत्र में पेश किया जा सकता है।

प्रस्तावित संशोधन के तहत दुर्घटना में किसी की मृत्यु होने पर मुआवजा राशि चार गुना बढ़ाकर एक लाख रुपए की गई है। वहीं 'हिट एंड रन' के मामले में गंभीर रूप से घायलों को 50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। संशोधन में ड्राइविंग लाइसेन्स, रजिस्ट्रेशन कार्ड, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट और आवेदनों के निपटान के संबंध में राज्यों के अधिकार बढ़ाने के प्रस्ताव भी शामिल हैं। *(दै.भा., 02.03.12)*

पर्यावरण

पर्यावरण पर ई-वेस्ट की तगड़ी मार

भारत के लिए आज एक बड़ी समस्या इलेक्ट्रॉनिक कचरा (ई-वेस्ट) है। यह न केवल हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है बल्कि कई खतरनाक बीमारियों का कारण भी बनता जा रहा है। इस कचरे को लेकर लचर नीतियों के चलते अमरीका सहित पश्चिम के देशों ने भारत को ई-वेस्ट खपाने का एक बड़ा स्थान बना लिया है। साथ ही भारत में भी पैदा हो रहे ई-वेस्ट को लेकर भी कोई ठोस रणनीति नहीं है। हर साल देश में 3,50,000 टन ई-वेस्ट जमा हो जाता है और 50,000 टन आयात होता है। सेकंड हैंड के नाम पर भी काफी कचरा देश में लाया जा रहा है। देश में 90 फीसदी यह कचरा गलत तरीके से रिसाइकिल होता है, जो बेहद नुकसान दायक है।

इसी साल ई-वेस्ट प्रबन्धन नियम 12 मई से लागू होगा, जिसमें कंपनियों की बजाय उपभोक्ताओं पर ज्यादा जिम्मेदारी होगी। हालांकि जो मानक बनाए जा रहे हैं अभी स्पष्ट नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने वाली कंपनियों के पास ई-वेस्ट को लेकर कोई नीति नहीं है। वे रिसाइक्लिंग की जिम्मेदारी से भी बचना चाहती हैं, पुराना माल भी धड़ल्ले से बेच रही है। *(रा.प., 11.03.12)*

उपभोक्ता फैसले

सही सेवाएं नहीं देने पर टैन्ट हाउस संचालक पर जुर्माना

नागौर के डीडवाना निवासी राम गोपाल अग्रवाल ने जयपुर में छोटी चौपड़ स्थित गोयल टेन्ट हाउस के खिलाफ उपभोक्ता मंच में परिवाद दायर किया। उन्होंने परिवाद में मंच को बताया कि वह स्टेच्यू सर्किल स्थित एक मैरिज लॉन बुक कराने के लिए टैन्ट हाउस संचालक से मिला था। संचालक ने लॉन बुक होने की बात कहते हुए, बनीपार्क स्थित राम मन्दिर के पीछे श्रीराम वाटिका लॉन बुक करने को कहा। लॉन एक लाख पांच हजार में बुक हुआ। टैन्ट संचालक ने वहां अच्छी व्यवस्था करने का वायदा किया था। लेकिन वायदे के मुताबिक उसने शादी के दिन लॉन में सही और पर्याप्त व्यवस्था नहीं की।

मामले की सुनवाई पर टैन्ट हाउस संचालक ने सफाई पेश करते हुए कहा कि लॉन में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थीं। परिवादी राम गोपाल ने मंच के सामने साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए टैन्ट संचालक के तर्क को गलत बताया।

प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर उपभोक्ता मंच ने तय शर्तों के अनुसार सही सेवा नहीं देने को सेवा दोष माना और टैन्ट हाउस संचालक पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। मंच ने यह राशि दो माह की अवधि में रजिस्टर्ड डाक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से परिवादी राम गोपाल अग्रवाल को अदा करने के आदेश दिए हैं। *(रा.प., 23.1.12)*

समय पर डाक नहीं पहुंचाई, देना होगा एक लाख 50 हजार का हर्जाना

नई दिल्ली निवासी एक छात्रा सईदा मदीहा ने जिला उपभोक्ता मंच, दिल्ली में डाक विभाग के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। उसने अपने परिवाद में बताया कि उसका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा का प्रवेश-कार्ड डाक से आना था, जो कि परीक्षा की तारीख निकल जाने के बाद उन्हें मिला। यह पत्र उन्हें यदि समय पर मिल जाता तो वह प्रवेश परीक्षा देने जा सकती थी और उसका कैरिअर बन जाता, लेकिन डाकघर की लापरवाही से ऐसा नहीं हो सका।

उपभोक्ता मंच में मामले की सुनवाई पर डाक विभाग की ओर से कहा गया कि विभाग इस मामले को लेकर खुद उलझन में है, और इस बात की जांच करवा रहा है कि प्रवेश कार्ड छात्रा तक समय पर क्यों नहीं पहुंचा। डाक विभाग की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि छात्रा का पता गलत था, किसी तरह पता लगाकर डाक सुपुर्द की गई थी। लेकिन यह तर्क सिद्ध नहीं हो पाया।

उपभोक्ता मंच ने समय पर डाक नहीं पहुंचाने को गंभीर लापरवाही के दायरे में लिया और डाक विभाग को आदेश दिया कि वह छात्रा सईदा को एक लाख 50 हजार रुपए का हर्जाना अदा करे। *(न.नु., 02.03.12)*

खास समाचार

उपभोक्ता संरक्षक कानून में संशोधन

उपभोक्ता संरक्षण कानून को अधिक सशक्त बनाने के मकसद से केन्द्र सरकार का कानून में संशोधन करने का मानस है। सरकार न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं करने पर 500 रुपए या कुल राशि की 1.50 फीसदी शास्ति संबधित संशोधन लाने पर विचार कर रही है। उपभोक्ता संशोधन विधेयक 2011 में प्रस्तावित कई संशोधनों में शास्ति संबधित यह संशोधन भी एक है।

इसके माध्यम से जानबूझकर कानून की अवहेलना करने वाले लोग सावधान हो जाएंगे। अब अधिकांश उपभोक्ता संरक्षण मंच कम्प्यूटराइज हो चुके हैं। मद्देनजर आनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी प्रस्तावित है। इससे उपभोक्ता ई-गवर्नेंस की दिशा में आगे बढ़ेगा। इसके अलावा एक अन्य संशोधन के जरिए जिला फोरम अथवा राज्य व राष्ट्रीय फोरम का निर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री की तरह होगा। *(न.नु., 09.01.12)*

सहकारी क्षेत्र से बंटेगी उपभोक्ता सामग्री

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गांवों में उपभोक्ता सामग्री के वितरण का जिम्मा ग्राम सेवा सहकारी समितियों को सौंपा जाएगा। इससे वितरण व्यवस्था प्रभावी व मजबूत होगी। यह समितियां राशन सामग्री के साथ अन्य उपभोक्ता सामग्री भी उचित मूल्य पर उपलब्ध करा सकेंगी। इसके लिए राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन का भी निर्णय लिया है।

वर्तमान में ग्रामीण स्तर पर प्रदेश में 5,400 से भी ज्यादा सहकारी समितियां काम कर रही है। नई समितियों के गठन के लिए मानदण्डों को आसान बनाया गया है। अब पांच लाख रुपए की हिस्सा राशि पर ग्राम सेवा समिति का गठन किया जा सकता है। सहकारिता विभाग ने इसके लिए इकाई अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। *(न.नु., 03.1.12)*

वितरण प्रणाली में आएगी पारदर्शिता

केन्द्र सरकार की ओर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कंम्प्यूटरीकरण कराया जा रहा है। इसके लिए 4000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजना बनाई जा रही है। इससे भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से राशन विक्रेता की दुकान तक सारे सिस्टम में परदर्शिता आएगी।

यह जानकारी केन्द्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के.वी. थॉमस ने देते हुए बताया कि सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून बनाया है। इससे यह जरूरी हो गया है कि इस व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। राशन के जरिए कई उत्पाद बेचे जाएंगे और उनकी कीमतें भी कम होगी। ऐसे में यह जरूरी है कि समूची प्रक्रिया पर पूरी निगरानी हो सके।

(न.नु, 04.01.12)

फोर्टिफाइड खाद्य आहार योजना शुरू

कुपोषण और खून की कमी से पीड़ित बच्चों व महिलाओं के लिए राज्य सरकार ने फोर्टिफाइड खाद्य आहार योजना शुरू की है। इसके तहत विटामिन व मिनरल वाला आटा, अनुपूरक शिशु आहार, दूध, तेल, नमक व दालों का उत्पादन व वितरण होगा। इनमें आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन-बी 12 और विटामिन-ए मिलाया जाएगा, जो कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है।

राजस्थान में 40 फीसदी से भी ज्यादा बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। इसमें सुधार के लिए सरकार ने यह योजना ग्लोबल एलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रीशन 'गेन' और भारतीय स्वास्थ्य प्रबंधन व शोध संस्थान के साथ मिल कर शुरू की है। लोगों को यह आहार कम कीमत पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलेंगे। *(दै.भा., 04.02.12)*

स्त्रोतः रा. प.: राजस्थान पत्रिका, दै. भा.: दैनिक भास्कर, न. नु.: नफा नुकसान, दै. न.: दैनिक नवज्योति, पं.के. पंजाब केसरी

पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोनः 91.141.513 3259 फैक्सः 228 2485, टेलीफैक्स: 401 5395, ई-मेलः cart@cuts.org, वेबसाईटः www.cuts-international.org के लिए जयपुर प्रिंटर्स प्रा. लि., जयपुर द्वारा मुद्रित।